

window is opened and new legislation might be brought in which will deprive them of any property.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Ganesh Ghosh. He might start and continue next time.

**Shri Ganesh Ghosh (Calcutta South):** I must start with a protest against the Chair for discriminating against my party.

**Shri Randhir Singh:** He should not say that. He should not asperse the Chair. He should respect the Chair. We all want we should have more time.

**Shri Sheo Narain:** The Chair is the supreme authority here. He must withdraw it.

**Mr. Deputy-Speaker:** There is no discrimination against any party. This is not a party issue. Shri Nath Pai has brought in this Bill not as one belonging to a particular party, but as a member of this House doing his duty. So do not think in terms of party. You can say whatever you have got to say without bringing this consideration.

**Shri Sheo Narain:** He must withdraw that remark.

**Mr. Deputy-Speaker:** He will

**Shri Ganesh Ghosh:** Some learned members on this side have spun many legal cobwebs to make a very simple proposition very complicated and almost unintelligible. The common people, the man in the street, will look at this as a simple thing and approach it from that standpoint.

What Shri Nath Pai wants to do is to amend art. 368 so that this Parliament can change any provision of the Constitution. Hon. Members of the Swatantra Party have vehemently opposed it. The reason for their opposition is quite intelligible and

understandable. But what is the opposition to?

We know that fundamental rights are enshrined in Part III of the Constitution. They are put in there. Though they are not up to our expectations, still they contain certain good things. But a cursory glance at them would convince you of the very strong emphasis put on the right to property. In the present condition of our society, is it not a fact that only those persons who have got some property have got the exclusive privilege to enjoy all the fundamental rights enumerated in Part III? This cannot be denied. In the fundamental rights is the proposition that all are equal before the law. But you must have property, movable or immovable, before you can approach the law court and claim justice or register your protest against an injustice done.

**Mr. Deputy-Speaker:** He might resume on the next occasion. We shall talk up the half an hour discussion now.

18 hrs.

#### \*PANDE COMMITTEE REPORT ON DURGAPUR STEEL PLANT

श्री सच्चिदानंद (मुंबई) उपाध्यक्ष महोदय, आज दुर्गापुर के इस्पात क रचना में जो खामिया हैं उनके ऊपर मैं बड़ा उदा रण हूँ। इस मामले में इस्पात मंत्रालय की मांगों पर बल नहीं होने वाली हैं क्योंकि बल लागू नारी मांगों पर मिलोटीन गया है।

सब से पहले मैं श्री महोदय से कहूँ कि मेरी सपना में नहीं आता है कि हिन्दुस्तान स्टील के द्वारा अपनी सालाना रपट पर इतना बज्जा कायदा क्यों खर्च किया जा रहा है क्योंकि यह रपट साल-साला घीर

## [श्री मधु सिमरने]

भारत-प्रशासक के प्रस्तावों और निजी इच्छा की बात पर आधारित नहीं है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में हम लोगों के सामने दो रपट हैं। एक पार्ले कमीशन की रपट और उससे पहले पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की रपट। इन दो रपटों में जो दोष, अनियमितताएँ, कमियाँ और खराबियाँ बतलाई गई हैं उनका प्रतिबिम्ब हिन्दुस्तान स्टील की ग्यारहवीं और बारहवीं रपट में विन्कुव रिपोर्ट नहीं देता है। इस रपट में केवल भारत-प्रशासक और भारत-प्रबंधक हैं। जैसे,

"One of Durgapur's main achievements last year was the reduction in consumption rates of major raw materials."

यह बात हिन्दुस्तान स्टील की वार्षिक रपट कहती है जब कि पार्ले कमीशन और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कहते हैं कि यह बात सही नहीं है और यह कि कच्चे मास का इतना ज्यादा इस्तेमाल और दुस्रुपयोग हो रहा है कि सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए।

इस ग्यारहवीं और बारहवीं वार्षिक रपट में साठ दोष मजदूर-व्यवस्थापक सम्बन्धों और झुलस तीर पर मजदूरों पर नज़र दिया गया है। उसमें कहा गया है कि मजदूरों ने हड़ताल की, मजदूरों ने संघर्ष किया और इसी लिए उत्पादन घट रहा है। मैं यह विवेचन करना चाहता हूँ कि यह बात सही नहीं है।

इस मंत्रालय के नीचे जितने सरकारी कारखाने हैं मंत्री महोदय उनके व्यवस्थापकों को हिदायत दें कि प्राइमिआ जो सालाना रपट वे देना करें, वह भारत-प्रशासक और भारत-प्रबंधक पर आधारित न हो बल्कि वे उनमें भारतीयों के आचार पर अपने दोषों और कमियों की कर्षा करें और साथ ही वह भी बतयें कि वे उन दोषों और कमियों को दूर करने के लिये क्या क्या कदम उठा रहे हैं।

यहां तक मजदूर-व्यवस्थापक सम्बन्धों का प्रश्न है, मेरा कयाल है कि मजदूर संघासय की मांगों पर जोखते हुए भी कई मासिक सम्बन्धों ने उनके बारे में क्या होना। पिछली सौक तथा में मैंने इस बाबत का एक विधेयक पेश किया था कि कारखानों में मजदूरों की युनियनों को प्रतिवर्ष कम से मासिक दोषों और अन्तर किसी कारखाने में एक से अधिक युनियनों हैं और इस बात पर अग्रवा होता है कि उन में से कौन सी अधिक प्रतिनिधिक है—क्योंकि दो या तीन युनियनों के प्रापसी झगड़ों को लेकर भी बहुत सी हड़तालों और झगड़ों हो रहे हैं—, तो यह खब करने के लिए दो साल में एक बड़ा मतदान, वीट किया जम्मे। लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की जो अनुमति चाहिए यह नहीं मिली।

मैंने फिर वह विधेयक पेश किया है और मुझे उम्मीद है कि या तो सरकार स्वयं इस काम को करेगी या मेरे विधेयक के सिद्धांतों को स्वीकार करेगी।

मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि रेलवे प्रावि जितने भी सरकारी कारखाने या संस्थान हैं, उनमें ट्रेड युनियन संगठनों की झुलस प्राज बहुत बराबर है। मुझे ऐसा धन्यता है कि व्यवस्थापक और सरकार कई युनियनों को खड़ा करने उनके नेताओं को धमक में खड़ा कर और कुछ लोगों को प्रयोग में दे कर यह चाहते हैं कि सरकारी संस्थानों में कोई मजदूर ट्रेड युनियन न हो। लेकिन मैं यह निर्देयन कर्षा कि यह सरकार की दूर-दृष्टि नहीं है। अन्तर निजी उद्योगों पर कारखाने या अंडरटेकिंग में एक मजदूर ट्रेड युनियन इन जायेगी, तो वह सरकार के पक्षकार, शिक्षक और बुधबला में सुधार के अर्थों में सहाय्य के सुदीनी।

परिष्कारित कमेटी की रपट में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि अगर कर्मियों की काम अच्छी तरह चला जा तो बहुत सारे खर्चे न होते। उस रपट में कई सुझाव दिये गये हैं। उस दिन श्री सिवारी ने कहा कि रिपोर्ट को दिये बार बार साज हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जो दुर्गापुर के बारे में रपट है, क्या उसके बारे में उन्होंने अपनी एक्शन टेकन रपट भेजी है।

श्री पांडे कमीशन की सिफारिशें आई हैं। उसने नौ-दस मामलों पर रोशनी डाली है। उन सब का तो मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। उसने बताया है कि 1965-66 में 3,21 लाख रुपये का मुकमान हुआ और 1966-67 में 13 करोड़ रुपये का मुकमान हुआ। उसका कहना है कि इन वर्षों में बीबाबार घटती घसी जा रही है और मुकमान बढ़ता जा रहा है।

आई-प्रोसेस के बारे में पांडे कमीशन ने कहा है :

"The performance so far has been very unsatisfactory except in the tar plant."

मेनटेनेंस के बारे में पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने कहा था कि उसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी तरह पांडे कमीशन ने भी कहा है :

"It is a matter of regret that maintenance which is a vital aspect of plant management has so far been sadly neglected at Durgapur."

कर्मों का काम का मैंने पहले ही उल्लेख किया है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के व्यवस्थापक अपनी रपट में कहते हैं कि हम ने

इसके बारे में बहुत तर्कों की हैं, लेकिन न तो पब्लिक अडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने इसको कबूल किया है और न पांडे कमीशन ने इसको कबूल किया है।

जहाँ तक मजदूर मालिक सम्बन्धों का सवाल है, सरकार इस बारे में कोई ठोस सुझाव सदन के सामने रखे और दुर्गापुर के व्यवस्थापकों को भी आवश्यक हिदायत दे, क्योंकि आज वहाँ पर हालत बहुत खराब है। मंत्री महोदय ट्रेड यूनियनों की मांगता और उनके मतदान का भी इंतजाम करे। अगर एक मजदूर यूनियन को मांगता दी जायेगी, तो वह उत्पादन और कार्य-क्षमता में वृद्धि के मामले में सहायता दे सकेगी।

पांडे कमीशन के ऊपर सवाल-जवाब के समय मैंने उसकी रपट में से थोड़ी बरीरह के तीन-चार उदाहरण पेश किये थे, लेकिन इन लोगों को थोड़ी के बारे में पता तक नहीं था।

मैं ने देखा है कि सरकार ने जनरल मैनेजर के खिलाफ कार्यवाही करने उनको हटाया है और शायद वह दो सुपरिन्टेंडेंट्स के खिलाफ भी कार्यवाही करने जा रही है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस कार्यवाही को रोकने के लिये अदालत का आवय लेकर अदालत के सामने ले गये और मुझे पता चला है कि रोक लग गई है। इसलिये जो नये जनरल मैनेजर उनसे काम का चार्ज लेने वाले थे, वह नहीं ले सके हैं। इसके बारे में मैंने बी वक्रा कहा है कि एक बड़ी गम्भीर घटना हो रही है। जब कभी कोई काम हाथ में लिया जाता है तो अदालतों और कानूनों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि अच्छे काम में रुकावट पैदा होती है तथा दूसरे ढंग से भी इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है—उसके बारे में भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ।

## [श्री मधु लिखारं]

इस कमीशन का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह वित्तीय व्यवस्था के बारे में है। इस कमीशन ने लिखा है—

"It is found that operation budget is being prepared only to obtain fund, authorisations and not for profit planning. The costs show a rising trend in most cases."

इस तरह मामला एक दम खराब हो रहा है। आपने बहुत धक्का किया कि पाण्डे कमीशन को सभी सिफारिशों को कुबूल किया है, लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूँ कि क्या हर दो महीने के बाद, या तीन महीने के बाद इन सिफारिशों पर धमक करवाने के हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई है, इसके बारे में इस सदन के सामने, हम मांगें या न मांगें, आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? जहाँ तक धमक का मामला है, धमक इस तरह से सदन को प्रवृत्त कराते जायेंगे तो हो सकता है कि धमका घटा बहुत हो, सबाल जबाब हो, इस तरह साल भर में हम लोगों को मौका मिलेगा और बोर्ड निगरानी भी हम रख पायेंगे और फिर वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं वे ठीक कायवाही करेंगे।

इस में बिस्नार के भी सबाल हैं। पब्लिक धण्डर टेंकिन कमेटी ने डिवाइजन ब्राई के बारे में, ठेका देने के बारे में कहा है कि कांट्रक्ट सिस्टम के बारे में पूरा विचार किया जाय कि किस तरह में दिया जाय। जब विस्तार पर आप विचार कर रहे हैं तो पब्लिक धण्डर टेंकिन कमेटी के सारे सुझावों पर भी आप विचार करे और जिस तरह से पाण्डे कमीशन के बारे में कहा, उसी तरह पी० यू० सी० को भी प्रवृत्त करायें और जो मतभेद के विषय हैं, उनको सदन के सामने लायें ताकि उनके बारे में हम अपना निर्णय दे सकें।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Fernandes.

Shri S. S. Kothari (Mandassur): Sir, my name is on the list. I am among those who have raised this discussion. The others come afterwards.

Mr. Deputy-Speaker: I would permit you to put one question. The rule about this is strict. Because your name appears in the list, that does not give you any right. But I will allow you to put a question.

Shri S. S. Kothari: The departments of the Durgapur steel plant appear to be vying with each other in the matter of touching the depths of inefficiency. There has been progressive deterioration with regard to production, sales, productivity, technical efficiency, cost control, inventory control, financial results, quality of production, achievement of the installed capacity and in various other departments. Actually, their budgets are almost aimless, they do not have any direction, they are not aimed at maximisation of profit, and the result has been that there has been a progressive increase in losses, amounting to about Rs 13 crores in 1966-67. Keeping in view this position and in order to achieve better results, greater efficiency and, I would say, a metamorphosis in administration and running of the concern, would the Government consider planning the budgets on the basis of a five year period, that is, a budget to be prepared on the basis of projected balance-sheets and profit and loss accounts for the next five years, compare the actuals with the budget and on the basis of variations, revise the future budgets? Besides, would he consider appointing a committee drawn from personnel in the other two plants to achieve basic changes or metamorphosis in working of the Durgapur steel plant?

श्री कंवर भाल सुप्त (दिल्ली सरर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, दुर्गापुर स्टील प्लांट  
द्वारा एक्सपेकर की सब से बड़ी ड्रेन है  
जहाँ करोड़ों रुपया मानी के खर्च बहावा  
जाता है। पांचे कमीशन ने कहा कि 13 करोड़  
रुपये का घाटा एक साल में हुआ है। प्रोबेशन  
में भी केवल एक चीज में जो 1963-64 में  
10.2 परसेन्ट थी, वह 66-67 में  
घट कर 6.4 परसेन्ट रह गई है।  
किस कमीशन ने उसके हर रिपोर्टमें  
के बारे में अपनी काफी रिक्मेन्डेशन दी  
है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रश्न चाहता हूँ  
कि क्या वह मेरे इस सुझाव पर विचार करेगे  
कि जो कर्मिया पांचे कमीशन ने हम  
स्टील प्लांट के बारे में बताई हैं वे कैसे दूर  
हो उन का एक फ्लेब-प्रोग्राम प्राप बनायें कि  
हर तीन महीने भौर 6 महीने के बाद इतनी  
इतनी कर्मिया दूर हो जायेंगे कुछ साल भर  
के दूर होंगे कुछ दो साल में दूर होंगी  
इस किस्म का प्रोग्राम बना कर सदन के सामने  
रख प्रौर कैंने कैंने वे कर्मिया दूर हो गईं  
कैसे कैंने उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ—  
इस सब की रिपोर्ट भी सदन के सामने क्वार्टली  
रखा जाय, ताकि सदन को यह विन्वास हो  
कि यह जो करोड़ों रुपया नानियो में बहावा  
जा रहा है यह ठक सकता है। अगर इस काम  
में बर्दा पर सरकार को कोई कर्नाई पेश  
आयो हो तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक्स-  
पॉरिमेंट साफिजन जो ईमानदार हों छांट कर  
पेजे जायें। इस तरह से यह गड़बड़ बन्द होनी  
चाहिये थी। इस नुस्त्रान को रोका जाना चाहिये।

श्री कर्ण कलेन्द्रोच्च (यम्बई-दक्षिण)  
उपाध्यक्ष महोदय, पांचे कमेटी की रिपोर्ट  
पर कई दिनों से सार्वजनिक रूप से बहस हो  
रही है तथा इस कारखाने को चलाने के सम्बन्ध  
में जो हमने कर्मिया हैं वे सब इन रिपोर्ट  
के हाग जनता की नजरों में था चुकी है।  
श्री, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानता हूँ कि  
सरकार ने इस कमेटी की सिफारिशों को  
मंजूर कर लिया है। लेकिन इस प्रकार की

सिफारिशें केवल दुर्गापुर ही नहीं बल्कि सभी  
सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के सम्बन्ध में  
हैं—इतनी बुनियादी बजह यह है कि इन  
कारखानों के चलाने वाले जो लोग हैं जो  
मैनेजमेंट के लोग हैं वे इसको अपनी विनाश  
समझ कर बताते हैं। इनके ऊपर किसी  
किस्म की देखरेख नहीं रहती है। जब मामला  
बहुत ही बिगड़ जाता है जैसे दुर्गापुर में  
बिगड़ गया, करोड़ों रुपये का नुकसान खुले  
तौर पर हमारे सामने पार गया तब एक-आध  
कमेटी बन जाती है, एक-आध कारखानों के  
बारे में जैसे दुर्गापुर में हुआ। वही चीज  
फर्टीलाइजर प्लांट में हो रही है वही पोपाल  
के हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाने में हो रही है  
वही चीज रांची के हैवी इंजीनियरिंग में हो  
रही है वही चीज एन० सी० डी० सी० में  
हो रही है, चाहे जिस कारखाने का नाम लीजिये  
यह बदमाशी, यह चोरी होती है। यह  
बजह एक ही यह है कि यह रिवासमेंट है।  
वह जो राजाशो को खत्म किया जिनकी कि  
प्रिवी परम के बारे में बहुत चर्चा है और यह  
नये राजा लोग इस कारखाने को चलाने से  
रुके हुए हैं थो मेरा इतना ही प्रश्न है कि रपट  
जकर भगाई लाये जाच जकर की जाच।  
सदन के सामने हर तीन महीने में छ महीने  
में एक आध रपट जकर दी जाय मगर इससे  
काम पूरा नहीं हो सकेगा। हम यह जानते  
हैं कि इन रपटों पर और उनकी भौर से भाई  
हुई किसी की मालुमात पर इस सदन में जिन  
गम्भीरता से पचा होनी चाहिए जितना बहुत  
उस चर्चा के लिए मिनता चाहिए उतना  
बहुत नहीं मिलाता है। इसलिए मैं मंत्री  
महोदय से या प्रश्न प्रश्नना चाहता हूँ कि जो  
पब्लिक इंडस्ट्रियल कमेटी हो वह कमेटी  
रहते हुए भी, वह कमेटी अपनी कार्य करती  
हुए क्या जो प्रलय प्रलय सार्वजनिक क्षेत्र  
के लिए यह बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं जिनमें  
करोड़ों रुपया, जनता के पैसे को हमने लगाया  
है, यह कर्मियों के व्यवसाय के बारे में  
इनके व्यवहार के बारे में और इनकी देखरेख

[श्री जार्ज फर्नेन्डीज]

के बारे में हमेशा के लिए जांच करने के लिए पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी, एक हमेशा की स्टीडिंग कमेटी बनाने के लिए क्या सरकार विचार करेगी और उस कमेटी को बनाने का काम करेगी ?

श्री रणबोर सिंह (रोहताक) : उपाध्यक्ष महोदय, हाथत यह है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों देना की। यह देश में कौमी मिक्चियन बढ़ाने का बँसे धाज एक बड़ा अवदन्त और सुहावना नारा है लेकिन भ्रमर पबलिक सैक्टर प्रडर-टैकिंग का यही हाल होगा जैसा देखने में आ रहा है तो यह देश के हित में नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूँ कि कहीं इनमें कोई साजिश तो नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि जिस चीज को भी हम कौमी मिक्चियत में लेते हैं उतारों घाटा दिखाया जाता है ? नहीं यह सरमायेदार, इजारेदार मैनिपुलेट न करते हैं और उनमें घाटा दिखाते हैं ? भ्रमर वार्कर्स में ऐसी कोई बात है साजिश है तो यह एक बड़ी गम्भीर बात है। हम ने बड़ी बड़ी सनघतों को कौमी मिलकियत में लिया है, उन को पबलिक सैक्टर में टेक-ओवर किया है वह इस तरह से लिया है कि देश को उसमें करोड़ों रुपयों का फायदा हो और वह देश के विकास में लगे लेकिन वह तो फिर मुझते ही भ्रमे पड़ने वाली बात देखने में आ रही है कि इन पबलिक प्रडर-टैकिंग में एक, एक साल में 13, 13 करोड़ रुपये का खसारा हुआ। यह देख कर हमें सन्न आती है। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दाल में काला है उकर। इस मामले की आप इन्मीजिएट कौगनिजेंस लीजिये। यह बहुत सीरियस मामला है। देश के भास के साथ देश के धन के साथ इस तरह का खिलवाड़ खेला जाय यह बहुत ही धनुचित व बेद की बात है। मैं कहना चाहूँगा कि न तो वहाँ इस्टिमिनेट ठीक है और न ही वहाँ सुपरविजन ठीक है। न वहाँ परसेवर प्रागेनाइजेशन है न कोई किसी

किस्म का लेबर को रैकगनीशन है। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस बारे में गम्भीरता से विचार करे और देखे कि यह प्रावधान क्यों है और भ्रमर वह हो तो गवर्नमेंट उसका इन्मीजिएटली इलाज क्यों नहीं करती ?

मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट यह जांच करे कि यह रोग क्या है ? भ्रतली वजह क्या है कि इतनी बड़ी प्रडरटैकिंग में दो, चार इतनी बड़ी प्रडरटैकिंग में इतना खसारा क्यों पड़ता है ? नेजबेज में देखें तो करोड़ों और प्रज्जों रुपयों का खसारा पाते हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार प्रमर्ल (२०००) के और जैना कि धर्मो मेरे एक साथी ने कहा और मैं उनकी बात से कतई इतिक्राक करता हूँ कि एक हार्ड-पावर्ड कमेटी पार्लियामेंट की इनको देखे या एक्सपर्टस कमेटी इसमें गहराई में जाय। मैं चाहता हूँ कि इस बीमारी को पकड़ा जाय और उसका माकूल इलाज हमेशा के लिए किया जाय। किसी भी छत्रे को तब तक नेमनसाइज न किया जाय जब तक उस से फायदा न हो वरना इस तरह से तो सारे देश का कौनफिडेस गोक हो जायगा।

इन पबलिक प्रडरटैकिंग में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई इटक या प्रन्च डिन्च मजदूर सभा या दूसरी लेबर यूनियन नहीं है जो कि मजदूरों के फायदे व हित को ध्यान में रख कर काम करती हों। भ्रमर बहा की लेबर यूनियन रैकगनाइज नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है ? बहा पर भी वरजसल सरमायेदारों की बात चल रही है। भ्रमर बहा पर इटक सरीखन कोई मजदूर संगठन नहीं बना है तो वह क्यों नहीं बना है और जो उन्हें न बनने देने के रास्ते में बाधा डालते हैं उनके खिलाफ प्राय क्या कोई ऐक्शन लेंगे ? उनका इटक सरीखा या और कोई प्रन्च मजदूर सभ मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए उनमें मजदूरों की कोई एक यूनियन प्रपन्च चाहिए और वह रैकगनाइज होनी चाहिए।

मैं आहूँगा हूँ कि एक प्रसल चीज देश के सामने होनी चाहिए और मजदूर के हित का

यहाँ पर ध्यान रखना जाना चाहिये। साथ ही पर्यवेक्षक का जो उत्तर है क्या काम है सरकार का वह सर्वोच्च है कि वह देखे कि उसका बंदीले धीरे सुपरवाइजन ऐसे हो ताकि यहाँ का काम ठीक तरह से चले धीरे वह मुनाफ़ा बिजनेसमें जो कि देश के काम में लगे। प्रायः जैसे जवान मिनिस्टर उस के इन्चार्ज हैं धीरे सारे देश की धरबो रूपों की जायबाब धापके सुपरवाइजन में है। जो भी कमी हो वह प्रायः हाउस को बतलाये ताकि उस कमी को दूर करके इस काम को ठीक लाईस पर चलाया जा सके धीरे सही तीर पर जैसा कि काग्रेस मनिंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि बड़े बड़े उद्योगों को कौमी मिलकियत में लिया जाय, उनको कौमी मिलकियत में लेकर देश को फायदा पहुंचाये धीरे जैसा कि हमारा मकसद है देश को हून समाजवाद के ध्येय की धीरे धारो से चले। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह इस बारे में जबाब दें।

श्री राम सेवक दास (बाराबंकी)  
सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों प्रायिकी हालत खराब है। मैं इस सिलसिले में पाण्डे प्रति-बेदन की इस रिपोर्ट की धीरे इसारा दिलाता चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि बुर्गापुर में जो 27 प्लांट हैं उन में मार्च सन् 1967 में 27 बेकार थे। 13 की प्रायश्यकता नहीं थी, 9 के रखरखाव का इन्तजाम नहीं था, 4 में डिमाइन् की कमी थी धीरे 1 का इस्तेमाल करना प्रायिकी दृष्टि से लाभदायक नहीं था। यह स्थिति है धीरे जब यह स्थिति हुई तो मैं जानना चाहता हूँ कि योजना में या कहा पर किस की जिम्मेवारी थी धीरे साथ ही साथ क्या उच्च धीरे भी मंत्री महोदय का ध्यान था कि जो धापके मौक़रसाह हूँ उनका बिषयवस्तु सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है धीरे ऊपर की भी निलकियत, राष्ट्रीय सम्बन्ध के प्रति धारा भी धरे नहीं है कि कहीं वह बर्बाद हो नहीं हो रही है धीरे एक यह स्थिति है धीरे धन धीरे धीरे ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय कोई इसका बिषय

सोचेंगे क्योंकि धरने कोई किसी कारखाना होता तो उस का दीखना निकल गया होता लेकिन धाज जनता के धीरे से दीखता नहीं निकलता है धीरे यह मौक़रसाह लोग बहा भीष कर रहे है धीरे गुलछरे उबा रहे हैं तो क्या मंत्री महोदय इस के ऊपर बिचार करेगे धीरे इस का क्या समाधान वह करने जा रहे हैं वह हाउस को बतलायेंगे ?

श्री हुक्म चन्द कल्याण (उज्जैन)  
मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कितना माल इस कारखाने को विदेश में निर्यात किया गया है इन चार सालों में धरने धीरे उन में से कितना माल खराब होने के कारण प्रायिकी हमारे यहाँ प्राया है धीरे उस में कितनी हानि हुई है ? उस के धरने क्या दृष्टि की जिम्मे कि कारण माल खराब हुआ धीरे क्या उस की जांच करके सम्बन्धित धफ़सरो के बिनाफा कोई कार्यवाही की जायगी ?

Shri Krishna Kumar Chatterji (Howrah): Is the Minister aware that during the life time of the late lamented Chief Minister of West Bengal, Dr. B C Roy, at the initial stage, when the conditions were going from bad to worse, he suggested to the Central Government that certain efficient officers from the State should be posted there, those officers who would be able to control the labour force there and bring about peaceful relationship between labour and management? Is he aware that those officers have been changed very frequently and thereby the conditions have deteriorated?

Shrimati Lakshminathanamma (Khammam): The Pande Committee report has said that some reforms in administration as in the Bhilai steel plant, have to be introduced in Durgapur. Have the Government accepted that recommendation?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the points raised by the hon. Members in the context of the Pande Committee report, I

[Dr. Chenna Reddy] should say, in general I welcome their constructive approach and the suggestions that they have made. The first point made by the hon. Member, Shri Limaye, is regarding the annual report and the way in which the problems are dealt with in the annual report. I should say that it is true that instead of talking merely in a general way, the problems should be properly analysed and the defects that are discovered, they should also be mentioned in the Annual Report and the management should make it a point to say in what manner they would tackle them and what improvements they are going to make. I will take note of his suggestion.

Regarding the labour unions, I entirely agree that there is considerable difficulty. We find it has become more and more difficult in view of the complicated claims which are arising. I do not blame anybody, neither any political party nor individual unions. I am trying to discuss with the labour leaders of all-India level, including that of AITUC, like Shri Dange and others, to see how best we could solve the problem, particularly in the public sector. Concern has been expressed in this House, and rightly so, that if the public sector in this country has come to a stage where it has lost the confidence of the people we should try to restore it so that people will have more and more confidence in it. In that way, we cannot tackle the malady which has been rightly stressed unless we have very good relationship between the management and the labour. I entirely agree with that.

As you will see, in the Pande Committee Report, certain points have made out. I do not want to blame any labour union. I am only trying to make a reference to what has been referred to in the Pande Committee Report which is now a matter for discussion now. It has been stated there that the welfare measures in the Durgapur Steel Plant cost Rs. 600 per year per employee which is about 25

per cent of the wages paid to the lowest-paid workers. Not only that. As has been pointed out, for various reasons, there is a planned absenteeism among the workers. As against 12 per cent in 1963-64, the absenteeism has risen to 18 per cent in 1966-65 and to 18.25 per cent in 1966-67. The incidence in Durgapur has been 1½ times that of in other steel plants. This is a very serious factor. This means there is a plan among the workers to get overtime.

Shri Kanwar Lal Gupta: What is the name of that union?

Dr. Chenna Reddy: There are two unions. One is Hindustan Steel Workers Union affiliated to INTUC and the other one is Hindustan Steel Employees Union affiliated to AITUC. The first union affiliated to INTUC was recognised in February, 1962. As you know, the recognition of the labour unions in these sectors is a matter for the State Governments and there are State labour laws which operate there.

श्री कांवर लाल गुप्ता : कोट प्राफ डिस्टिन्ट केन्द्रीय सरकार का है और केन्द्रीय सरकार के ही अधिकार में है मान्यता देना ।

Dr. Chenna Reddy: The point is that the Industrial Labour Dispute Act as operated by the Central Ministry while the recognition of the labour unions is done by the State Governments.

I had an occasion to go into the realities as to what is the actual position that exists. I discussed it recently with one of the Chief Ministers of a State where we have one of the public sector units. I would like to make it absolutely clear that I do not propose to blame anyone. It is inherent in the situation. I am only trying to find out in what manner we can evolve an ideal management-labour relationship.

Some suggestions made by my hon. friend, Shri Madhu Limaye, are really worth consideration and, in that context, I have already taken it up with the Labour Minister and also with the labour leaders. It will be really a step in the right direction if we can try to do something substantial which can create a good atmosphere.

Then, there are one or two more points that have been stated by a number of hon. Members, that is, how do you deal with the recommendations of the Pande Committee. Report I must say that we are very earnest about it. We want to do our best. I should also join with the hon. Member, Shri Randhir Singh, when he said that it is a matter of shame that there has been so much loss, that I am really pained to say that a public sector unit has lost about Rs. 13 crores a year. I am not really happy about it. It will be our earnest effort and I seek the guidance of the hon. Members of this House in this effort to see that if we can try to improve the situation. When the Pande Committee Report came, we have never hesitated, without any reservation, in accepting most of the recommendations. Where we found we could not accept the recommendations, we placed before the House how and for what reasons those recommendations could not be accepted.

The suggestion made by Shri Gupta and also stated by Shri Madhu Limaye appears to be a very practical one, that is, how we can plan out the implementation of the recommendations made by the Pande Committee Report. I would like to assure the House, in order to ensure that the necessary improvements are brought about speedily, Government intends to arrange for periodical reviews of the practical steps taken to give effect to these recommendations and, to go a step further, how a particular recommendation can be implemented within three months, how a particular recommendation can be implemented within six months or in a year or in two years. I would like to assure the

House that we shall try to make an exercise and try to find out how we can plan it out. The only point is whether it would be practicable to place, every three months, these details on the Table of the House. I have no reservation and am not trying to keep anything behind. It may not be possible to do it every three months. I can only say that I will examine that aspect and in whatever manner I can place the progress of the implementation of the recommendations, I will certainly come to the House and place the necessary information on the Table of the House.

A suggestion was also made about budget. Hon. Member, Mr. Kothari, made a very good suggestion. He asked what was the plan and how do we have it. I may say that the HSL has been asked to fix targets of production, quality and costs for each plant. An elaborate plan has been drawn up and we shall have quarterly reviews to ensure that we can take preventive steps in good time before things take an ugly shape as has happened in the case of Durgapur. I entirely agree; I am one of those who feel that the autonomy should not be extended beyond a certain logical reality and we should not allow things to go in this manner. After all, the Government and this hon. House have every right, have every responsibility, to see that the money is properly utilised and the economic activity is properly shaped. I would like to assure this hon. House that we would like to check these production targets and all that; we will have a periodical review and see that before things become bad, we have a proper checking of these things.

Regarding General Managers and certain other staff, I do not like to take the time of the House nor have I time at my disposal. A number of times, this House and several Committees of this House have expressed their anxiety about Government not taking necessary action when certain things come to light. On the 2nd or

[Sri Chenna Reddy]

3rd June when the question came up for discussion, some hon. members, particularly Mr. Madhu Limaye—I have those questions and answers before me—asked what action we had taken and how did we propose to take action. It was in that light and also in appreciation of the anxiety and also in appreciation of our responsibility to see that there shall not be any feeling that some of the senior people who are left with the responsibility of looking after the organisations, irrespective of their behaviour, can just have their own way, we took action. It was very painful for us. All the same, we examined very carefully and tried to fix the responsibility. Action has been taken against three of them. One officer has already resigned and gone away. Another officer, who has been served with the notice of termination of services, has also quit. Only the General Manager has resorted to this action. I do not like to say anything more. I generally feel that in a matter of this type, there should be certain things, they should feel that they are responsible; otherwise, severe action will be taken against them.

**Shri S. S. Kothari:** They should be prosecuted, if they do not behave properly.

**Dr. Chenna Reddy:** We have started this. If the public opinion and this hon. House give us this kind of encouragement and support, we can take the right action. I would like to assure the House that Government will certainly take a serious view of these things whenever they arise.

श्री हुकम चन्द्र कल्याण : मेरे सवाल का क्या हुआ ?

डा० चन्ना रेड्डी : उस पर अभी घा रह है ।

**Mr. George Fernandes** made a suggestion that there should be a special Standing Committee of Members of Parliament. I do not know whether there can be any other Committee

when there is a Committee on Public Undertakings which is really looking after these things. If the Committee on Public Undertakings makes any suggestion or if the hon. House, in its wisdom, feels that there should be some such Committee, I, as the Minister concerned with this portfolio where we have a large number of public sector units, would not grudge, I would welcome it. But, I do not feel competent to say anything about it.

श्री जार्ज फरनेन्डीस ने इतना ही सूचना करू कि पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के सिमामिने मे मैं जानता हू कि वह साल मे चार या पाच कारखानों की रिपोर्ट तैयार करती है। जैसे रेनवे की जीवन कंगल्टेडिव कमेटी बनती है और वह बिल्कुल बेकार होती है, लेकिन प्राप एम० पी० लोगों को उसी मे भेजते हैं। मैं जानना चाहता हू कि प्राप क्यों ऐसी कमेटियां कारखानों के लिये नहीं बनाते जो उन की देख रेख करें और तत्काल प्रश्न उठाए ।

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon Member has raised a fundamental question because nowadays Parliament functions more through committees. He wants a type of Standing Committee or something of that type. The Minister has said that he would consider.

**Dr. Chenna Reddy:** There were certain other suggestions. Mr. Chatterji made a reference to the fact that the officer should be there for a long time. In fact, we have been trying to keep this in mind. The present General Manager has been there for about 2½ years continuously. He belongs also to the same State in which this plant is located. Therefore, we hope and it is our expectation also that there will be better relationship between the management and the labour. That is how we have been trying to improve the relation between the labour and the management.

Shrimati LakshmiKanthamma suggested that what was happening in Bhilai or some other places should be put into practice in the Durgapur Steel Plant also. In fact, we want to do not only that, but we want to see that there is some kind of a co-ordinated attempt. We are having certain reorganisation of details in our view and we want that the experience of one plant which is good should be applied to the other plants also on the same lines. That will be our objective.

If I had more time, I would have dealt with some more points.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे मवान का जवाब तो दिया ही नहीं।

Dr. Chenna Reddy: Actually, the figures in regard to the export from the Durgapur plant are not really available. But most of our figures indicate that all the things are utilised in our own country.

श्री हुकम चन्द कछवाय : प्रतिवारी मब बैठ हुए हैं। वे आपको ये आकड़े दे मन्ने थे।

मैं ने कहा था कि जो सारा माल गया है उससे कितनी हवारी बदनामी हुई है। हमारा माल वहा से बायिन आया है। उसके आकड़े मैंने पूछे है।

Mr. Deputy-Speaker: He has given the reply already.

Dr. Chenna Reddy: Let me make it very clear that there is no question of any bad reputation of our product. Firstly, our exports have been very small, being only of the order of Rs 1 to 2½ crores; last year, the figure had gone up to Rs 28 crores, and this year we are hoping to reach the target of Rs 50 crores. From nowhere has there been any complaint about quality. I do not know if the hon. Member has any information in this regard. I can assure him that I do not want to be dogmatic about it. If he has any information, I shall certainly take notice of it and take the information from him.

18.42 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, July 22, 1967/Asadha 31, 1889 (Saka)